ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 151
ANSWERED ON 21/12/2022

MGNREGA FUNDS RELEASED AND DUES

151 SHRI JAWHAR SIRCAR:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of States that have not been given any funds under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) in this financial year and the reasons therefor;
(b) the funds released to each State for MGNREGA during this Financial Year as compared to last year;
(c) the reasons why MGNREGA budget has been kept so low despite huge pending dues; and
(d) funds released in current year for past dues, and for new works?

ANSWER
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

Statement in reply to Parts (a) to (d) of Rajya Sabha Starred Question No. 151 for 21.12.2022.

(a): Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (Mahatma Gandhi NREGS) is a demand driven wage employment Scheme. Fund release to the States/UTs is a continuous process. As per the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, it is the responsibility of the State Government to ensure transparency and accountability in the implementation of the scheme. Also, according to the provision of the scheme, if the State Government is not fully successful in discharging its responsibility, then the Government of India has the right to issue appropriate guidelines as well as stop the release of funds. Accordingly, funds have not been given to only one State under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in the current financial year 2022-23.

(b): Funds released to States/UTs for implementation of Mahatma Gandhi NREGS during current Financial Year 2022-23 and last Financial Year 2021-22 is at **Annexure**.

(c): Mahatma Gandhi NREGS is a demand driven wage employment programme. The amount is released as per the requirement of the fund as per the demand.

(d): During current Financial Year 2022-23, an amount of Rs. 2,671 crore has been released for previous year's dues and Rs. 41,663 crore has been released for new works towards wages.

****

Annexure referred in reply to part (b) of Rajya Sabha Starred Question No. 151 dated 21.12.2022.

State/UT-wise details of fund released under Mahatma Gandhi NREGS in the last financial year 2021-22 and current financial year 2022-23 (as on 14.12.2022) (Rs. in lakh)

Sl. No.	State/UT	2021-22	2022-23
1	Andhra Pradesh	721442.94	626040.27
2	Arunachal Pradesh	45628.27	35988.96
3	Assam	238324.81	150361.62
4	Bihar	543992.91	463161.76
5	Chhattisgarh	390619.75	149582.33
6	Goa	24.46	396.47
7	Gujarat	161561.03	137838.75
8	Haryana	72752.60	27501.57
9	Himachal Pradesh	98470.29	97054.10
10	Jammu & Kashmir	96317.21	53458.13
11	Jharkhand	307663.40	130873.96
12	Karnataka	606401.95	443998.48
13	Kerala	346901.56	240223.46
14	Madhya Pradesh	849990.43	425651.43
15	Maharashtra	207596.99	185564.51
16	Manipur	56310.74	75649.62
17	Meghalaya	113765.51	74462.42
18	Mizoram	55018.16	34961.24
19	Nagaland	57501.18	54529.11
20	Odisha	571332.31	367886.81
21	Punjab	127146.82	83818.97
22	Rajasthan	988655.74	615903.25
23	Sikkim	11267.32	6291.12
24	Tamil Nadu	964220.53	661760.74
25	Telangana	423808.58	241024.52
26	Tripura	99644.08	74856.71
27	Uttar Pradesh	855134.38	770692.84
28	Uttarakhand	64613.11	56959.79
29	West Bengal	754591.22	0.00
30	Andaman & Nicobar	763.16	461.41
31	Lakshadweep	30.05	0.00
32	Puducherry	1410.77	1931.32
33	Ladakh	5904.89	3470.18
34	Dadra & Nagar Haveli & Daman & Diu	0.00	80.93
Total		**98,38,807.15**	**62,92,436.80**

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 151*

(21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत जारी की गई धनराशि और देनदारियां

***151: श्री जवाहर सरकारः**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस वित्तीय वर्ष में कितने राज्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कोई धनराशि नहीं दी गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) भारी मात्रा में लंबित देनदारियों के बावजूद मनरेगा के बजट को इतना कम रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछली देनदारियों और नए कार्यों के लिए चालू वर्ष में कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

राज्य सभा में दिनांक 21.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 151 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के प्रावधानों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन मे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही योजना के प्रावधानों के अनुसार अगर राज्य सरकार अपनी इस जिम्मेदारी के निर्वहन मे पूर्णरूपेण सफल नहीं होती है तो भारत सरकार को समुचित दिशानिर्देश जारी करने के साथ ही निधि के निर्गत करने को रोकने का अधिकार है। इसके अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत केवल एक राज्य को निधि नहीं दी गई हैं।

(ख): वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 और पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां अनुबंध में दी गई हैं।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। मांग के अनुरूप निधि की आवश्यकता के अनुसार राशि निर्गत की जाती है।

(घ): वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मजदूरी मद में पिछले वर्ष की बकाया राशि के लिए 2,671 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और नए कार्यों के लिए 41,663 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

*****

राज्य सभा में दिनांक 21.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 151 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित

वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 (14.12.2022 तक) और पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	721442.94	626040.27
2	अरुणाचल प्रदेश	45628.27	35988.96
3	असम	238324.81	150361.62
4	बिहार	543992.91	463161.76
5	छत्तीसगढ़	390619.75	149582.33
6	गोवा	24.46	396.47
7	गुजरात	161561.03	137838.75
8	हरियाणा	72752.60	27501.57
9	हिमाचल प्रदेश	98470.29	97054.10
10	जम्मू और कश्मीर	96317.21	53458.13
11	झारखंड	307663.40	130873.96
12	कर्नाटक	606401.95	443998.48
13	केरल	346901.56	240223.46
14	मध्य प्रदेश	849990.43	425651.43
15	महाराष्ट्र	207596.99	185564.51
16	मणिपुर	56310.74	75649.62
17	मेघालय	113765.51	74462.42
18	मिजोरम	55018.16	34961.24
19	नागालैंड	57501.18	54529.11
20	ओडिशा	571332.31	367886.81
21	पंजाब	127146.82	83818.97
22	राजस्थान	988655.74	615903.25
23	सिक्किम	11267.32	6291.12
24	तमिलनाडु	964220.53	661760.74
25	तेलंगाना	423808.58	241024.52
26	त्रिपुरा	99644.08	74856.71

27	उत्तर प्रदेश	855134.38	770692.84
28	उत्तराखंड	64613.11	56959.79
29	पश्चिम बंगाल	754591.22	0.00
30	अंडमान और निकोबार	763.16	461.41
31	लक्षद्वीप	30.05	0.00
32	पुदुचेरी	1410.77	1931.32
33	लद्दाख	5904.89	3470.18
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	80.93
कुल		**98,38,807.15**	**62,92,436.80**

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, as it will appear from the reply, there has been a gross injustice against West Bengal that has not been given even one paisa under NREGA this year, not a single paisa, against Rs. 7,500 crores given last year! So, I wanted to know from the hon. Minister why such a special favour has been meted out, why such a special spite has been meted out in spite of the fact that the Chief Minister has ordered that every Job Card be verified.

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय के प्रश्न पर स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। सरकार 'मनरेगा' के तहत किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है, लेकिन केन्द्र सरकार के कुछ रूल्स होते हैं, जिनका राज्यों को अनुपालन करना चाहिए। यदि सदन का ज्यादा समय वेस्ट न हो, तो मैं कुछ उदाहरण जरूर देना चाहूंगी।

MR. CHAIRMAN: Be brief.

साध्वी निरंजन ज्योति : महोदय, पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार को वर्ष 2019 में केन्द्रीय दल के द्वारा की गई निरीक्षण जांच रिपोर्ट पर व्यापक एटीआर देने हेतु कई बार आग्रह किया गया, किन्तु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा उस पर उचित कार्यवाही नहीं की गई।...(**व्यवधान**)... अंततः हमारे द्वारा एटीआर भेज दी गई, जिसकी जांच जारी है।...(**व्यवधान**)...

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, it is a lie. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Jawhar Sircar, you will get your turn. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय सभापति महोदय, एक अन्य केन्द्रीय दल द्वारा योजना में...(**व्यवधान**)... माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह राजनैतिक प्रश्न है, तो जवाब भी राजनैतिक होगा।...(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, wait for your turn. ...*(Interruptions)*... Let the hon. Minister reply. ...*(Interruptions)*...No. Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

साध्वी निरंजन ज्योति : आप जवाब सुनने की क्षमता रखिए।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Take your seat. ...*(Interruptions)*... You will get an opportunity. ...*(Interruptions)*...

साध्वी निरंजन ज्योति : एक अन्य केन्द्रीय दल द्वारा योजना में वर्ष 2019 की तरह ही कदाचार पाया गया, अतः ...(**व्यवधान**)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, it is a political reply. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You will get your right. ...*(Interruptions)*... Mr. Sukhendu Sekhar Ray, you will get your right. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय सभापति महोदय, हम गरीबों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*...Hon. Minister. ...*(Interruptions)*...

साध्वी निरंजन ज्योति : राज्य सरकार, भारत सरकार के जो रूल्स हैं, उनका अनुपालन करे, तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Sircar, your second supplementary. ...*(Interruptions)*...

श्री जवाहर सरकार : आप मुझे बात करने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member will ask his second supplementary. ...*(Interruptions)*... Please listen to the hon. Member. ...*(Interruptions)*... It is an important issue. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, the hon. Minister has made a very exaggerated one-sided response. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Ask your supplementary. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAWHAR SIRCAR: I can prove it. ...*(Interruptions)*... We can prove every word of it. ...*(Interruptions)*... This is political discrimination before our Panchayat elections and you will face it now. ...*(Interruptions)*...

Sir, second supplementary is: Why are you killing NREGA? Sir, from Rs. 1.17 lakh crores two years before, you have brought it to Rs. 1 lakh crores last year and

now you have brought it to Rs. 62,000 crores? ...*(Interruptions)*...You are reducing it by 30 per cent! ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister will reply. ...*(Interruptions)*...

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।...(**व्यवधान**)... पश्चिमी बंगाल के लिए आपने धन को रिलीज़ करने की बात पूछी है, तो मैं थोड़ा पीछे भी जाना चाहूंगी।...(**व्यवधान**)... 2006 से 2014 तक पश्चिमी बंगाल के लिए 14,985 करोड़ रुपये एलोकेट हुए थे।...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... I am here to deal with everything. ...*(Interruptions)*...

साध्वी निरंजन ज्योति : पश्चिमी बंगाल को यह धनराशि दी गई थी।...(**व्यवधान**)... माननीय सभापति महोदय, 2014 से अब तक पश्चिमी बंगाल को 54,150 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)... राज्य सरकार नियमों का अनुपालन करे। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्ज़ हैं।

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)' के तहत देश भर में कुल कितने मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? इस सम्बन्ध में गुजरात राज्य का जिलावार ब्यौरा देने का कष्ट करें।

साध्वी निरंजन ज्योति : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो राष्ट्रीय स्तर मजदूरों का ब्यौरा मांगा है, यदि अभी मैं पिछले और वर्तमान के बारे में बोलूं, तो मुझे लग रहा है कि 2014 के पहले 2006 से 2014 तक 1,660 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया। उसके अलावा माननीय प्रधान मंत्री जी के शपथ लेने के बाद 2014 से अभी तक हम लोगों ने इसमें बहुत बढ़ोतरी की है। इसमें हमने 2006 से 2014 तक 2,13,220 करोड़ रुपये निधि जारी की, जबकि 2014 से अब तक 5,79,783 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

श्री रामजी : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी से ...

MR. CHAIRMAN: Put your question, please.

डा. जॉन ब्रिटास : सर, कुछ कंफ्यूजन है, यह प्रश्न 154 है?

MR. CHAIRMAN: No, no. On this, you have to ask your supplementary.

SHRI RAMJI: Sir, I have to ask supplementary on Question No. 154, not on this.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, it is me who has to put the question. There is some confusion. He has to ask supplementary on Question No. 154 and I am on 151.

MR. CHAIRMAN: But I had your request, Shri Ramji.

DR. JOHN BRITTAS: That is for Q. No. 154, Sir.

MR. CHAIRMAN: No. Shri Ramji, your request was for Q. No. 151. Doesn't matter. Okay. Now, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, thank you for having given me this opportunity. In respect of MNREGA funds, the Central Government has released thousands of crores to the State of Andhra Pradesh. There are huge complaints from the executants and cases have been filed against….

MR. CHAIRMAN: Ask your question.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Several members have filed complaints that the dues are not paid to the executants. That is why, they have filed a number of cases before the High Court. Then only they released part payment and contempt cases are also pending before the High Court.

MR. CHAIRMAN: Put your question please.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, I am coming to that. There are also a large number of complaints sent to the Ministry. My question to the hon. Minister is: Has the Ministry initiated any inquiry about the misuse of MNREGA funds in the State of Andhra Pradesh or not?

साध्वी निरंजन ज्योति : महोदय, माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछा है। राज्य सरकार के साथ केन्द्र सरकार समन्वय करके काम करना चाहती है, लेकिन कुछ राज्यों में केन्द्र सरकार की शर्तों के आधार पर काम न होने के कारण कार्य में विलम्ब होता है। यदि कहीं ऐसा है, तो हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि 'मनरेगा' जैसी एक बहुत प्रभावी योजना यह सरकार लागू करने का काम कर रही है। मेरा सवाल यह है कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि करीब 341 ब्लॉक्स में 'मनरेगा' के कामों को लेकर अनियमितताएं पाई गई हैं और यदि अनियमितताएं पाई गई हैं, तो कितनी धनराशि इसमें शामिल है? क्या इसकी जांच करने के लिए कोई विशेष ऑडिट टीम बनाकर रिपोर्ट ली गई और अगर रिपोर्ट ली गई, तो उसमें क्या पाया गया और इसमें सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

साध्वी निरंजन ज्योति : महोदय, यह मोदी जी की सरकार है, देश के हित में कोई भी योजना हो, हम उसे खत्म नहीं करते हैं। 'मनरेगा' के तहत हमने कोविड-19 के समय में कामगारों को अधिक पैसा पैसा दिया है और जहां तक जांच की बात है, यह राज्य सरकारों का विषय है, जैसे ही वहां से रिपोर्ट आती है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Next question. Question No. 152, Ms. Indu Bala Goswami. Supplementary one.